



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 14, मंगलवार, शाके 1930-अगस्त 5, 2008
Sravana 14, Tuesday, Saka 1930-August 5] 2008

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(युप 2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 5, 2008

संख्या प.2(39)विधि/2/2008-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त, 2008 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा

परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण)

अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 24)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त, 2008 को प्राप्त हुई]

चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मीयों के विरुद्ध हिंसा और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं में संपत्ति के नुकसान को प्रतिषिद्ध करने के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।

यतः राज्य में चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मीयों को क्षति या संकट कारित करने और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के हिंसात्मक कार्य होते रहे हैं जिससे राज्य में चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में विक्षोभ उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवाओं में बाधा होती रही है;

और यतः उक्त अपराधों को संज्ञेय और अजमानतीय बनाकर ऐसे हिंसात्मक क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक हो गया है;

अतः अब भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2008 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह 4 जून, 2008 को और से घवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) 'चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं' से लोगों को चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने वाली वे समस्त संस्थाएँ अभिप्रेत हैं जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकायों आदि के नियंत्रण के अधीन हैं, और उसमें सम्मिलित है रूग्ण व्यक्तियों के उपचार के लिए सुविधाएं रखने वाला और उन्हें प्रवेश देने या ठहराने के लिए प्रयुक्त कोई प्राइवेट अस्पताल; ऐसा प्राइवेट प्रसूति गृह जहां सामान्यतया महिलाओं को शिशु जन्म या उससे संसक्त किसी बात के संबंध में परिरोध और प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात् की परिचर्या के प्रयोजन के लिए प्रवेश दिया और ठहराया जाता है और किसी भी रूग्णता, क्षति या शैथिल्य, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, से पीड़ित व्यक्तियों को प्रवेश देने और ठहराने के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित प्राइवेट नर्सिंग होम जो उपचार या परिचर्या या दोनों उपलब्ध कराते हैं और उसमें कोई प्रसूति गृह या आरोग्य-गृह आदि सम्मिलित है।

(2) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था के संबंध में 'चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

- (क) चिकित्सा परिचर्या संस्थाओं में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका अनंतिम रजिस्ट्रीकरण हो गया है);
- (ख) रजिस्ट्रीकृत नर्स;
- (ग) चिकित्सा छात्र;
- (घ) नर्सिंग छात्र; और
- (ङ) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं में नियोजित और कार्यरत सह-चिकित्सा एवं अन्य सहकर्मी।

(3) 'अपराधी' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो या तो स्वयं या व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन के किसी सदस्य या मुखिया के रूप में इस अधिनियम के अधीन कोई हिंसा कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है या उसे करने के लिए उकसाता है।

(4) 'हिंसा' से चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिचर्या कर्मी या रोगी को कोई अपहानि करने, क्षति कारित करने या उसके जीवन को संकटापन्न करने या उसको अभित्रास, अवरोध या प्रतिबाधा कारित करने वाले या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की संपत्ति को नुकसान कारित करने वाले क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं।

3. हिंसा का प्रतिषेध.—चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों के विरुद्ध हिंसा का या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में संपत्ति को कोई नुकसान कारित करने वाला कोई भी कृत्य इसके द्वारा प्रतिषिद्ध किया जाता है।

4. शास्ति.—ऐसा कोई भी अपराधी जो धारा 3 के उल्लंघन में कोई भी कृत्य कारित करता है, तीन वर्ष की अवधि के कारावास और ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

5. अपराध का संज्ञान.—धारा 3 के अधीन कारित प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

6. संपत्ति को कारित नुकसान के लिए हानि की वसूली.—(1) धारा 4 में विनिर्दिष्ट दण्ड के साथ-साथ अपराधी, अपराधी का विचारण कर रहे न्यायालय द्वारा यथा अवधारित क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपस्करों के क्रय मूल्य और सम्पत्ति को कारित हानि की रकम के दुगुने की शास्ति का दायी होगा।

(2) यदि अपराधी ने उप-धारा (1) के अधीन शास्तिक रकम का संदाय नहीं किया है तो उक्त रकम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के उपबंधों के अधीन ऐसे वसूल की जायेगी मानो यह उससे भू-राजस्व की बकाया के रूप में शोध्य थी।

7. अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

8. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

एस.एस. कोठारी
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, August 5, 2008

No.F.2(39)Vidhi/2/2008.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Chikitsa Paricharya Sevakarmi Aur Chikitsa Paricharya Seva Sanstha (Hinsa Aur Sampatti Ke Nuksan Ka Nivaran) Adhinyam, 2008 (2008 Ka Adhinyam Sankyank 24):—

(Authorized English Translation)

**THE RAJASTHAN MEDICARE SERVICE PERSONS
AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS
(PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO
PROPERTY) ACT, 2008**

[Received the assent of the Governor on the 3rd day of August, 2008]

An

Act

to prohibit violence against Medicare Service Persons and Damage to Property in Medicare Service Institutions and for matters connected there-with and incidental thereto.

Whereas there have been acts of violence of causing injury or danger to life of Medicare Service Persons and damage to property of Medicare Service Institutions in the State creating unrest in Medicare Professionals resulting in hindrance of such service in the State;

And whereas, it has become necessary to prohibit such violent activities by making the offences as cognizable and non-bailable;

Now, therefore, be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2008.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 4th June, 2008.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(1) 'Medicare Service Institutions' means all institutions providing medicare to people which are under the control of State or Central Government or Local Bodies etc., including any private hospital having facilities for treatment of the sick and used for their reception or stay; any private maternity home where women are usually received and accommodated for the purpose of confinement and ante-natal care in connection with child birth or anything connected therewith; and any private nursing home used or intended to be used for the reception and accommodation of persons suffering any sickness, injury or infirmity whether of body or mind, and providing of treatment or nursing or both of them and includes a maternity home or convalescent home, etc.

(2) 'Medicare Service Persons' in relation to a Medicare Service Institution, shall include,—

- (a) Registered Medical Practitioners, working in Medicare Institutions (including those having provisional registration);
- (b) Registered nurses;
- (c) Medical students;
- (d) Nursing students; and
- (e) Para medical and other auxillary workers employed and working in Medicare Service Institutions.

(3) 'Offender' means any person who either by himself or as a member or as a leader of a group of persons or organization commits or attempts to commit or abets or incites the commission of violence under this Act.

(4) 'Violence' means activities of causing any harm, injury or endangering the life or intimidation, obstruction or hindrance to any medicare service person in discharge of duty in the Medicare Service Institution or patient or damage to property in the Medicare Service Institution.

3. Prohibition of violence.—Any act of violence against Medicare Service Persons or damage to property in a Medicare Service Institution is hereby prohibited.

4. Penalty.—Any offender who commits any act in contravention of section 3, shall be punished with imprisonment for a period of three years and with fine, which may extend to fifty thousand rupees.

5. Cognizance of offence.—Any offence committed under section 3, shall be cognizable and non bailable.

6. Recovery of loss for the damage caused to the property.—In addition to the punishment specified in section 4, the offender shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipments damaged and loss caused to the property as determined by the Court trying the offender.

(2) If the offender has not paid the penal amount under sub-section (1), the said sum shall be recovered under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No.15 of 1956) as if it were an arrear of land revenue due from him.

7. Act not in derogation of any other law.—The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law, for the time being in force.

8. Repeal and Savings.—(1) The Rajasthan Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Ordinance, 2008 (Ordinance No.2 of 2008) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

एस.एस. कोठारी,

Principal Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
गृह (मुप-5) विभाग

क्रमांक: प. 9(17)गृह-5/2017

जयपुर, दिनांक : 15.09.2017

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय : चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के प्रति बढ़ती हिंसक घटनाओं की रोकथाम एवं चिकित्सकों व चिकित्सालयों की सम्पूर्ण सुरक्षा के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि पिछले कुछ समय से चिकित्सकों के विरुद्ध कई हिंसक घटनाएँ घटित हो रही हैं। चिकित्सक वर्ग में इससे रोष है। राज्य सरकार के लिए यह भी चिन्ता का विषय है क्योंकि इससे न केवल चिकित्सकों का मनोबल गिरता है बल्कि मरीजों को दी जाने वाली आवश्यक सेवाएँ भी बाधित होती हैं। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ द्वारा चिकित्सा विभाग को प्रस्तुत मांग पत्र में सेवारत चिकित्सकों ने मांग की है कि "चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के प्रति बढ़ती हिंसक घटनाओं की रोकथाम एवं चिकित्सकों व चिकित्सालयों की सम्पूर्ण सुरक्षा हेतु स्पष्ट एवं प्रभावी नीति बनाई जावे"।

सेवारत चिकित्सकों की उक्त मांग के संबंध में राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मियों और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2008 दिनांक 04 जून, 2008 से लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम की धारा 3 में चिकित्सक परिचर्या सेवा कर्मियों के विरुद्ध हिंसा या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान में सम्पत्ति को नुकसान कारित करने वाला कोई भी कृत्य प्रतिषिद्ध किया गया है तथा कारित प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय है।

अतः उक्त अधिनियम के प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(अशोक जैन)

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

शासन सचिव, गृह

जयपुर
15.09.17

13/3/19

**कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा,
राजस्थान**

क्रमांक. सीआईडी / सीबी / पीआरसी / 2019 / 5763-5840

दि. 12.03.2019

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर एवं जोधपुर,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी., राजस्थान।

विषय: चिकित्सकों एवं अस्पतालों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए
हिंसक हमलों / दुर्व्यवहार के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य में प्रायः कुछ घटनाएं चिकित्सकों पर हमले / दुर्व्यवहार की हुई हैं, जिनमें हिंसा व सम्पत्ति को नुकसान की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। ये घटनाएं सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त अन्य प्राईवेट अस्पतालों में भी घटित हुई हैं। इन घटनाओं में प्रभावी कार्रवाई के लिए आवश्यक है कि ऐसी घटनाओं में दर्ज होने वाली एफआईआर में चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम 2008 की समुचित धाराओं को भी शामिल किया जाए। वर्तमान में ऐसा नहीं करने से इसका लाभ आरोपियों को मिल रहा है।

अतः समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को पाबंद करें कि वे चिकित्सकों / चिकित्सा परिसरों में घटित हिंसक / दुर्व्यवहार की घटनाओं में चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम 2008 की धाराएं अनिवार्यतः जोड़ें व तदानुसार कार्रवाई करें।

12/3/19
(गौरव श्रीवास्तव)

उप महानिरीक्षक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. महानिदेशक पुलिस, ATS एवं SOG, प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस (कार्मिक), राजस्थान।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला बीकानेर एवं भीलवाड़ा को भेजकर विशेष उल्लेख है कि हाल ही में आपके जिलों में दर्ज इस प्रकार के अभियोग में उक्त अधिनियम की धाराओं का उपयोग करना सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

2284
13/3/19

गिरि
12
Mugawast
2396
13.3.19

13/3/19

☎: +91-141-2740873

☎: +91-141-2740682

✉: adgn.crimebranch@rajpolice.gov.in

चेतावनी

राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी
और चिकित्सा परिचर्या सेवा (हिंसा और
सम्पति के नुकसान का निवारण)

अधिनियम 2008 (धारा-3)

चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था के निम्नलिखित
सेवाकर्मी सम्मिलित होंगे।

1. रजि. चिकित्सक ।
2. रजि. नर्सिज ।
3. चिकित्सा छात्र ।
4. नर्सिंग छात्र ।
5. सहचिकित्सा अन्य कर्मी ।

उपरोक्त चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मीयों के विरुद्ध हिंसा मारपीट
या तोड़फोड़ या सम्पति को नुकसान कारित करने वाला कोई भी
कृत्य करने पर निम्नलिखित सजा का प्रावधान है।

1. तीन वर्ष का कारावास ।
2. 50 हजार रु का जुर्माना ।
3. नष्ट हुई सम्पति की दुगुनी रकम का जुर्माना ।
4. जमानत का ना होना (NON BAILABLE)